[ 2016 ; 11 एस. सी. आर 15

" इन आरईः पंजाब समझौता अधिनियम की समाप्ति,

2004 "

( 2004 का विशेष संदर्भ सं. 1)

10 नवंबर, 2016

[ अनिल आर. डेव, पिनाकी चंद्र गौस, शिवा कीर्ति

सिंह, आदर्श कुमार गोल और अमिताव रॉय, जे. जे।]

भारत का संविधानः

कला. 143 पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता के संबंध में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने 31 दिसंबर, 1981 को एक समझौता किया, जिसमें उक्त राज्यों में से रावी और ब्यास जल के पुनः आवंटन पर सहमति व्यक्त की गई-समझौता पंजाब राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया-उच्चतम न्यायालय के समक्ष हरियाणा राज्य द्वारा मुकदमा, पंजाब राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र का निर्वहन करने का निर्देश देता है।

1981 के समझौते के तहत दायित्व-पंजाब राज्य द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया-आदेश को लागू करने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा निष्पादन याचिका की अनुमति दी गई-हालाँकि, पंजाब राज्य ने 1981 के समझौते को समाप्त करते हुए पंजाब समाप्ति समझौते अधिनियम, 2004 को लागू किया और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को भी रद्द कर दिया-अभिनिर्धारित किया गयाः पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 को कानूनी और वैध नहीं माना जा सकता है।

मुकदमे का एक पक्ष एक अदालत द्वारा पारित डिक्री के प्रभाव को कम करने के लिए एकतरफा तरीके से कार्य नहीं कर सकता है-एक मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति अपने कारण से न्यायाधीश नहीं बन सकता है 1981 का समझौता रावी और ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में था और इस प्रकार समझौते के किसी भी पक्ष द्वारा अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके एकतरफा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता था-पंजाब राज्य की 1981 के समझौते को समाप्त करने या देश के सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री को रद्द करने की ऐसी एकतरफा कार्रवाई भारत के संविधान के विपरीत है-अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956।

एस। 14 - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 - धारा. 78-पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर भूमि (स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण) अधिनियम, 2016।

Art.143-के तहत संदर्भ-तथ्य या तथ्य के सवाल पर होना

कानून का प्रश्न-आयोजितः कला का एक नंगे अवलोकन। 143 यह दर्शाता है कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को कानून या तथ्य का एक प्रश्न संदर्भित करने के लिए अधिकृत है, जो उसकी राय में ऐसी प्रकृति का और इतना सार्वजनिक महत्व का है कि इसे प्राप्त करना समीचीन है।

15 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 201

6 ] 11 एस सी आर।

इस पर उच्चतम न्यायालय की राय-अनुच्छेद राष्ट्रपति को केवल एक शुद्ध प्रश्न पर राय प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है

कानून।

कला. 143 - के तहत संदर्भ-क्या सर्वोच्च न्यायालय

अपनी राय देने के लिए बाध्य या नहीं-आयोजितः यह सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर है, कुछ मापदंडों के अधीन, यह तय करना कि किसी संदर्भ पर किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना है या नहीं।

संदर्भित प्रश्नों का नकारात्मक में उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 को कानूनी और वैध नहीं माना जा सकता है और पंजाब राज्य इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपने कर्तव्यों/देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है।

31 दिसंबर, 1981 के समझौते के बारे में। [ पैरा 31] [34-ई-एफ]

1.2 यह विवादित नहीं था कि पंजाब राज्य और इलारियाना राज्य के बीच एक मुकदमा था और अंततः एक डिक्री बनाई गई थी जिसके तहत 1981 के समझौते के अनुसार पानी के बंटवारे के संबंध में व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार उक्त व्यवस्था के लिए एक कानूनी मंजूरी थी और एक बार कानून के न्यायालय द्वारा एक बाध्यकारी डिक्री पारित किए जाने के बाद, मुकदमे का एक पक्ष एकतरफा रूप से डिक्री के प्रभाव को रद्द करने के लिए इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है। [ पैरा 32] [34-एफ-जी]

1.3 तत्काल मामले में, संपर्क करने के बजाय

पंजाब अधिनियम ताकि डिक्री के प्रभाव को रद्द किया जा सके। यह ध्यान देने योग्य है कि जल विवाद, जिसे पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य ने किया था, 1956 के अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण को भेजा गया था। संबंधित प्रावधानों पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने एक न्यायिक निर्णय लिया था और उक्त निर्णय को 2004 के पंजाब अधिनियम के अधिनियमन के आधार पर बाधित करने की भी मांग की गई है। [ पारस 33,39] [34-जी-एच; 38-ए

बीजे

1.4 एक वादी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। 1981 का समझौता रावी के पानी के बंटवारे के बारे में था और

ब्यास नदियाँ। उक्त समझौते को समझौते के एक पक्ष द्वारा आईएन आरई का प्रयोग करके एकतरफा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता थाः

पंजाब समझौता अधिनियम की समाप्ति,

2004

इसकी विधायी शक्ति और यदि कोई दल या कोई राज्य ऐसा करता है, तो किसी विशेष राज्य की एकतरफा कार्रवाई को भारत के संविधान के साथ-साथ 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत घोषित किया जाना चाहिए। [ पारस 36,39] [36-एफ; 38-बी-सी]

1.5 उपर्युक्त कारणों से, 2004 का पंजाब अधिनियम ऐसा नहीं कर सकता है।

भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कहा जाए और उक्त अधिनियम के आधार पर पंजाब राज्य ऊपर निर्दिष्ट निर्णय और डिक्री को रद्द नहीं कर सकता है और 1981 के समझौते को समाप्त करें। [ पैरा 41] [38-ई]

रीः कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (1993) 1 सप.

तमिलनाडु बनाम। केरल राज्य और एक अन्य (2014) 12 एससीसी 696: 2014 ( 12 ) एस. सी. आर. 875-- पर निर्भर था।

2012 का सं. 1 (10) एस. सी. सी. 1: 2012 ( 9 ) एससीआर 311 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

2012 ( 9 ) एससीआर 311

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

1991 ( 2 ) पूरक। एससीआर 497

उस पर भरोसा करें

2014 ( 12 ) एससीआर 875

पैरा 34

सलाहकार न्यायनिर्णयः 2004 का विशेष संदर्भ सं. 1।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत। रंजीत कुमार, एस. जी., राम जेठमलानी, आर. एस. सूरी, जगदीप धनखड़,

श्याम दीवान, जे. एस. अत्री, सी. एस. वैद्यनाथन, सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनीश कुमार गुप्ता, अनिल ग्रोवर, एस. एस. शमशेरी, ए. ए. जी. एस. , एस. वसीम ए. कादरी, सुश्री माधवी दीवान, अजय शर्मा, जैद अली, एस. एस. रावत, सुश्री अनिल कटियार, प्रबल बागची, आकाश जिंदल (सुश्री सुषमा सूरी और डी. एस.

अवस्थी, वैभव अस्थाना, देवाशीष भरुका, रवि भरुका, सुश्री अर्पिता बिश्नोई, चंद्र शेखर सुमन, सुश्री दीपशिखा भाटी, सुश्री प्रियंका परिदा, वरिंदर कुमार शर्मा, चंद्र नंद झा, विक्रमजीत बनर्जी, अमित शर्मा, सुश्री रुचि कोहली, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री मेहर देव (सुरेश चंद्र त्रिपाठी के लिए), सुनील फर्नांडीज, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री पुनीत केजी, सुश्री मिथु जैन, दिनेश कुमार गर्ग, अधिवक्ता। , उपस्थित दलों के लिए।

[ 2016 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

एनिल आर. डेव, जे. 1. 22 जुलाई, 2004 के एक संदर्भ द्वारा, भारत के राष्ट्रपति ने एक सलाहकार राय के लिए अनुरोध किया

पंजाब राज्य द्वारा पंजाब समझौते की समाप्ति अधिनियम, 2004 (इसके बाद "पंजाब अधिनियम" के रूप में संपादित) के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत।

2. विचार के लिए निर्दिष्ट संदर्भ का पाठ

इस न्यायालय का न्यायालय इस प्रकार हैः

" सिंधु बेसिन में सिंधु नदियाँ शामिल हैं,

झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।

जहाँ 1960 में सिंधु जल संधि की गई थी

19 तारीख को भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सितंबर, 1960, जिसके तहत भारत रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के स्वतंत्र, अप्रतिबंधित उपयोग का हकदार है।

वे अंत में पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं;

जबकि उक्त संधि पर हस्ताक्षर करने के समय सतलुज के पानी का उपयोग भाखड़ा-नंगल परियोजना, रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त प्रवाह के लिए करने की योजना पहले से ही बनाई गई थी।

1955 में संबंधित राज्यों के बीच समझौते द्वारा विभाजन से पहले के उपयोग के अलावा, निम्नानुसार आवंटित किया गया थाः

अर्थात्ः

पंजाब

7.20 एमएएफ

( पेप्सू के लिए 1:30 एमएएफ सहित) राजस्थान

8.00 एमएएफ

जम्मू और कश्मीर

0.65 एमएएफ

15.85 एमएएफ

पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) जिसके परिणामस्वरूप पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य बनाए गए और इसका निर्धारण करना आवश्यक हो गया। पानी की मात्रा में से उत्तराधिकारी राज्यों के संबंधित हिस्से जो उपरोक्त ई के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैंः

पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में उपयोग के लिए आवंटन और जब उत्तराधिकारी राज्य किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे, तो केंद्र सरकार द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के तहत 24 मार्च, 1976 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत हरियाणा राज्य को 3.5 एमएएफ मात्रा में पानी आवंटित किया गया था।

जबकि उक्त 1976 की अधिसूचना के तहत हरियाणा राज्य को 3.5 एमएएफ पानी के आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए, सतलुज-यमुना लिंक नहर (जिसे इसके बाद एसवाईएल नहर कहा जाता है) का निर्माण हरियाणा राज्य द्वारा 1976 की अधिसूचना के बाद अपने हिस्से में शुरू किया गया था। एस. वाई. एल. नहर का निर्माण भी पंजाब ने अपने हिस्से में अस्सी के दशक की शुरुआत में शुरू किया था।

जहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने दिनांक 31.12.1981 पर समझौता किया, जिसके द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने समग्र राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए

जल के हित और इष्टतम उपयोग के लिए राज्यों के बीच जल के पुनः आवंटन पर निम्नानुसार सहमति बनीः

पंजाब का हिस्सा

4.22 एमएएफ

:

हरियाणा का हिस्सा

3.50 एमएएफ

राजस्थान का हिस्सा

8.60 एमएएफ

;

निर्धारित मात्रा

दिल्ली की जल आपूर्ति के लिएः

0.20 एमएएफ

जे एंड के का हिस्सा

0.65 एमएएफ

:

कुल

17.17 एमएएफ

जबकि उपरोक्त 1981 के तहत भी इस पर सहमति बनी थी।

समझौता कि एस. वाई. एल. नहर परियोजना को अधिकतम दो साल की अवधि के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख ताकि हरियाणा राज्य अपने आवंटित हिस्से का पानी निकालने में सक्षम हो। यह समझौता पानी के आवधिक वितरण को तय करने के लिए उपयोग में है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य;

जहाँ "पंजाब समझौता" नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे [2016] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24 जुलाई, 1985 को पंजाब राज्य से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए;

जबकि पंजाब समझौते के पैराग्राफ 9.1 में प्रावधान है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को रावी ब्यास प्रणाली से कम से कम पानी मिलता रहेगा, हालांकि उपभोग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी भी अप्रभावित रहेगा और दावा किए गए उपयोग की मात्रा को पैराग्राफ में निर्दिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

9.2 उस समझौते के बारे में जिसके तहत शेष जल में अपने हिस्से के संबंध में पंजाब और हरियाणा के दावों को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

चूंकि 'पंजाब समझौता' के पैराग्राफ 9.1 और 9.2 को प्रभावी बनाने के लिए अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 में धारा 14 जोड़ी गई थी, जिसके तहत ई. आर. ए. डी. ट्रिब्यूनल

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों द्वारा दावा किए गए पानी के उपयोग की मात्रा के सत्यापन के लिए गठित उनके शेष जल में शेयरों के बारे में। न्यायाधिकरण ने जनवरी, 1987 में एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों और केंद्र सरकार के संदर्भ

अगस्त, 1987 में अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ये संदर्भ न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं

चूंकि 'पंजाब समझौता' के अनुच्छेद 9.3 के तहत यह भी सहमति हुई थी कि एस. वाई. एल. नहर का निर्माण जारी रहेगा और इसे 15 अगस्त, 1986 तक पूरा कर लिया जाएगा। चूँकि एस. वाई. एल. नहर को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि जुलाई, 1990 में परियोजना के मुख्य अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता की हत्या के बाद काम रुक गया था और बाद में पंजाब सरकार द्वारा फिर से शुरू नहीं किया गया था और हरियाणा राज्य ने पंजाब क्षेत्र में एस. वाई. एल. नहर को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष 1996 का मुकदमा संख्या 6 दायर किया था।

इसका आदेश दिनांक 15.01.2002,31.12.1981 समझौते पर भरोसा करके और पंजाब राज्य को एस. वाई. एल. नहर ई. बनाने का निर्देश दिया गयाः

पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्यात्मक; जहाँ पंजाब राज्य ने एस. वाई. एल. नहर के निर्माण के दायित्व के निर्वहन/विघटन की मांग करते हुए एक मुकदमा (2003 का ओ. एस. नंबर 1) दायर किया था और 2003 का ओ. एस. नंबर 1 मुकदमा इस माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। भारत संघ को एक महीने की अवधि के भीतर नहर के कार्यों का नियंत्रण लेने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी को जुटाने का निर्देश दिया गया था और पंजाब राज्य को उसके बाद दो सप्ताह के भीतर केंद्रीय एजेंसी को काम सौंपने का निर्देश दिया गया था।

12 जुलाई, 2004 को पंजाब राज्य ने पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 (जिसे पंजाब अधिनियम, 2004 कहा गया है) लागू किया है, जिसमें पंजाब सरकार को दिनांकित समझौते 31.12.1981 और रावी-ब्यास के पानी से संबंधित अन्य सभी समझौतों के तहत अपने दायित्वों से समाप्त और निर्वहन किया गया है।

15 जुलाई, 2004 को भारत संघ ने बाद के तथ्यों को दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया और

माननीय के आदेश के पारित होने के बाद के घटनाक्रम

उच्चतम न्यायालय दिनांक 1 और माननीय न्यायालय से न्याय के हित में ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करने का अनुरोध किया;

पंजाब अधिनियम, 2004 और इसके प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के संबंध में संदेह व्यक्त किए गए हैं। और यह भी कि क्या 31.12.1981 दिनांकित समझौते को पंजाब राज्य द्वारा वैध रूप से समाप्त कर दिया गया है और क्या पंजाब राज्य को उक्त समझौते से कानूनी रूप से मुक्त कर दिया गया है।

समझौता; और जबकि उपरोक्त को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ है

अवांछनीय परिणाम और यह कि कानून का एक सवाल उत्पन्न हुआ है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है जो उस पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन; [2016] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अब, इसलिए, मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) द्वारा, भारत के राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम एतद्द्वारा निम्नलिखित का उल्लेख करते हैं - विचार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न और

उस पर रिपोर्ट करें, अर्थात्ः

i) क्या पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 और उसके प्रावधान इन प्रावधानों के अनुसार हैं।

दिनांक 24 मार्च, 1976 को इसके तहत जारी किया गया; iii) क्या पंजाब राज्य ने रावी-ब्यास जल से संबंधित दिनांकित समझौते और अन्य सभी समझौतों को वैध रूप से समाप्त कर दिया था और अपने दायित्व से मुक्त हो गया है।

उक्त समझौते के तहत; और iv) क्या अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए; पंजाब राज्य को दिनांकित 15.01.2002 के निर्णय और डिक्री और दिनांकित निर्णय और आदेश से अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है।

4.6.2004 भारत के सर्वोच्च न्यायालय "।

3. जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल उपस्थित हुए और इस संबंध में परिचयात्मक प्रस्तुतियाँ दीं

संदर्भ और उसके बाद, 2 अगस्त, 2004 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने भारत संघ और पंजाब, हरियाणा राज्यों को नोटिस जारी किए,

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अपने-अपने मुख्य सचिवों के माध्यम से। 4. वस्तुतः, इस न्यायालय को निर्दिष्ट मुद्दों पर हमारी राय देने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक तथ्यों को संदर्भ में विधिवत शामिल किया गया है और परिस्थितियों में, हम तथ्यों को दोहराकर अपनी राय का बोझ नहीं उठाना चाहेंगे। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के आधार पर इस न्यायालय को पंजाब अधिनियम, 2004 की वैधता की जांच करनी है और हमें यह भी जांचना है कि क्या पंजाब राज्य ने 31 दिसंबर, 1981 के समझौते और रावी-ब्यास जल से संबंधित अन्य समझौतों को वैध रूप से समाप्त कर दिया था ताकि उसे उन दायित्वों से मुक्त किया जा सके जो उसे उपयुक्त अधिकारियों द्वारा पारित कुछ वैध आदेशों के तहत निभाने थे। हालांकि, आईएन आरई के लिए:

पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

आगे स्पष्टता के लिए हम कुछ मुकदमों के संबंध में तथ्यों को संक्षेप में शामिल कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैंः

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने 31 दिसंबर, 1981 को एक समझौता किया, जिसका उल्लेख किया गया हैः इसके ऊपर संदर्भ में, जिसके आधार पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों ने समग्र राष्ट्रीय हित और रावी और ब्यास के पानी के इष्टतम उपयोग को देखते हुए रावी और ब्यास के पानी के पुनः आवंटन पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन क्योंकि उक्त समझौते पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी

पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस न्यायालय के समक्ष 1996 का मुकदमा संख्या 6 स्थापित किया था, जिसमें पंजाब राज्य और भारत संघ को शामिल किया गया था, जिसमें अन्य राहतों के अलावा निम्नलिखित की मांग की गई थीः

" ( क) यह घोषणा करते हुए एक डिक्री पारित करें कि 24-3-1976 का आदेश, 31-12-1981 का समझौता और 24-7-1985 का निपटान हैं

पंजाब राज्य पर अंतिम और बाध्यकारी

प्रतिवादी 1 पर सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के हिस्से को तुरंत फिर से शुरू करने और पूरा करने का दायित्व है और न केवल 1976 के उपरोक्त आदेश, 1981 के समझौते और 1985 के समझौते के तहत बल्कि 1976 से अब तक के आचरण द्वारा स्थापित अनुबंध के अनुसार भी इसे सभी मामलों में उपयोग करने योग्य बनाना है।

( बी) प्रतिवादी 1 (जो प्रतिवादी 2 किसी भी एजेंसी द्वारा या उसके माध्यम से विफल रहता है) को मजबूर करने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करें

1976 की उक्त अधिसूचना, 1981 के समझौते और 1985 के समझौते के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन और किसी भी मामले में आचरण द्वारा स्थापित अनुबंध के तहत, सतलुज-यमुना लिंक के उस हिस्से को तुरंत फिर से शुरू करके और पूरा करके

पंजाब राज्य में नहर परियोजना और अन्यथा इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना।

इस माननीय न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए

रावी और ब्यास के पानी का उसका हिस्सा;

5. यह न्यायालय सभी कानूनी पहलुओं और प्रावधानों की जांच करने के बाद,

1996 के उक्त वाद सं. 6 में दिनांक 15 जनवरी, 2002 के निर्णय के माध्यम से एक डिक्री पारित की गई, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे निकाला गया हैः

" 18. ..... राज्य सरकारों ने प्रवेश किया है

देश के प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप पर आपस में समझौते, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में लंबित मुकदमों को वापस लिया जाता है, को [2016] 11 एस. सी. आर. के विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपस में हुए समझौतों पर। हम भी हैं। माना जाता है कि यह देखना केंद्र सरकार का गंभीर कर्तव्य था कि समझौते की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाए। इसके अलावा, रुपये से अधिक। 700 जब हरियाणा के क्षेत्र के भीतर नहर का पूरा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है और उक्त नहर का बड़ा हिस्सा नहर के भीतर है, तो करोड़ों रुपये के सार्वजनिक राजस्व को नाले में बहने नहीं दिया जा सकता है।

यह भी पूरी तरह से निराधार है क्योंकि पानी निकालने का स्रोत केवल जलाशय से है, जो पंजाब के क्षेत्र के भीतर स्थित है और पानी की एक बूंद नहर में तब तक नहीं बहती जब तक कि जोड़ने वाले दरवाजे खुले हैं। लेकिन हरियाणा राज्य के पक्ष में पहले से आवंटित पानी की मात्रा को निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए और यह केवल तभी खींचा जा सकता है जब अतिरिक्त लिंक नहर पूरी हो जाए क्योंकि मौजूदा भाखड़ा मुख्य नहर में केवल 1.62 एम. ए. एफ. की आपूर्ति करने की क्षमता है।

पानी। यह स्थिति होने के कारण, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि

वादी-हरियाणा राज्य ने एस. वाई. एल. नहर के हिस्से को पूरा करने के लिए पंजाब राज्य के खिलाफ अनिवार्य रूप से निषेधाज्ञा जारी करने का मामला बनाया है, जो अधूरा है और यदि पंजाब राज्य इसे पूरा करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार-प्रतिवादी 2 को इसे पूरा करने तक देखना चाहिए, ताकि जो पैसा पहले ही खर्च किया जा चुका है और जो पैसा आगे खर्च किया जा सकता है, उसका कम से कम देशवासियों द्वारा उपयोग किया जा सके। हमने एक प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व, सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति और चोट के दृष्टिकोण से सामग्री की जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि वादी उपरोक्त मानदंडों में से प्रत्येक को स्थापित करने में सक्षम है और इस तरह वह मांगे गए निषेधाज्ञा का हकदार है।

के लिए। तदनुसार इस मुद्दे का जवाब वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ दिया जाता है। इसलिए हम एक अनिवार्य आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-पंजाब राज्य को सतलुज-यमुना लिंक नहर की खुदाई जारी रखने का निर्देश देते हैं, जिसका एक हिस्सा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आज से एक साल के भीतर नहर को चालू कर दें। हम भारत सरकार को आरई में भी निर्देश देते हैं:

पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

प्रतिवादी 2 अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए

खुदाई के संबंध में उपरोक्त निर्देश का कार्यान्वयन यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर एस. वाई. एल. नहर नहीं है

प्रतिवादी द्वारा पूरा किया गया-पंजाब राज्य, फिर संघ सरकार को इसे अपनी एजेंसियों के माध्यम से करना चाहिए।

पहले से ही खर्च किया जा चुका है और जो अभी भी खर्च किया जाना है, नहीं होगा बर्बाद हो जाएगा और वादी-हरियाणा राज्य सक्षम होगा

पानी के पुनः आवंटन के मामले में, किसी भी अतिरिक्त पानी को अनुदान देता है हरियाणा राज्य को, तो यह जारी करने पर भी विचार कर सकता है

कितना पानी हो सकता है, इसके बारे में उचित निर्देश एस. वाई. एल. नहर के माध्यम से खींचा गया।

19. वादी का मुकदमा उपरोक्त शर्तों पर तय किया जाता है। वहाँ

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

[ जोर दिया गया]

6. पंजाब राज्य ने 15 तारीख के फरमान का पालन नहीं किया

मार्च, 2002। 18 दिसंबर, 2002 को हरियाणा राज्य द्वारा दिनांकित निर्णय और डिक्री को लागू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था15.01.2002 और उक्त आवेदन 2002 के आई. ए. सं. 1 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

7. 13 जनवरी, 2003 को; पंजाब राज्य ने मुकदमा संख्या 1 दायर किया

2003 इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों की मांग की गई हैः

( क) एस. वाई. एल. नहर के निर्माण के दायित्व का निर्वहन/विघटन करना।

इस माननीय द्वारा घोषित अनिवार्य निषेधाज्ञा द्वारा अधिरोपित

न्यायालय ने ओएस संख्या 6/1996 में अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 15.01.2002 में शिकायत में बताए गए कारणों के लिए;

( ख) यह घोषित करना कि ओएस में 15.01.2002 दिनांकित निर्णय/डिक्री

नहीं. 6/1996 बाध्यकारी या लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि मुद्दे उठाए गए हैं।

उस वाद में केवल एक संविधान पीठ [2016] 11 एस. सी. आर. द्वारा निर्णय लिया जा सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( ग) यह घोषित करना कि अधिनियम, 1956 की धारा 14 भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; ( घ) यह घोषणा करना कि अधिनियम, 1956 की धारा 14 अब वाद में निर्धारित कारणों से प्रवर्तनीय नहीं है;

मुक़दमे में: वैकल्पिक रूप से;

यदि इस माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पंजाब समझौता

दिनांकित 24.07.1985 एक लागू करने योग्य समझौता है फिर निर्देशित करें अन्य 10 मुद्दों के साथ प्रवर्तनीयता और अनुपालन और अन्य शर्तों तक एस. वाई. एल. नहर के निर्माण के दायित्व को बनाए रखना।

समझौते में निर्धारित किए गए प्रावधानों को लागू किया जाता है और/या रावी-ब्यास के पानी के पुनः आवंटन से उत्पन्न होने वाले जल विवाद हैं

अधिनियम, 1956 के तहत हल किया गया।

( च) घोषणा करें कि अधिनियम, 1966 की धारा 78 (1) भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और सभी कार्य, कार्य और कार्य किए गए हैं।

उसके अनुसार या उसके परिणामस्वरूप सभी सहित

अधिसूचनाएँ, समझौते आदि अमान्य हैं जिनमें शामिल हैं -

अधिसूचना दिनांक 24.03.1976 और समझौता दिनांकित

31.12.1981 शुरुआत में गैर-पूर्व और शून्य के रूप में।

8. 4 जून, 2004 के निर्णय और आदेश द्वारा; यह न्यायालय

पंजाब राज्य द्वारा दायर किए गए मुकदमे का निपटारा किया और हरियाणा राज्य द्वारा दायर किए गए निष्पादन की अनुमति दी और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को पारित किया।

" 96. धारा 51 (ई) के तहत अवशिष्ट शक्ति एक अदालत को एक डिक्री को इस तरह से लागू करने के लिए आदेश पारित करने की अनुमति देती है जो इसे प्रभावी बनाएगी। पंजाब द्वारा नहर को पूरा करने के लिए डिक्री में निर्दिष्ट अवधि लंबे समय से समाप्त हो चुकी है। भारत संघ ने कहा है कि उसने इस दौरान एक आकस्मिक कार्य योजना तैयार की थी

अवधि। जनवरी 2003 में एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के रूप में आकस्मिकता हुई है। हमें यह नहीं बताया गया है कि आकस्मिकता योजना को लागू किया गया है या नहीं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना पर कैबिनेट समिति मूल्यांकनकर्ताओं ने एस. वाई. एल. ई. को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी:

पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

बी. आर. ओ. द्वारा नहर और 20-2 पर जल्द से जल्द बुलाई गई बैठक में

1991 , तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि बी. आर. ओ.

एस. वाई. एल. नहर को न्यूनतम समय में पूरा करने का कार्य संभव है, बी. आर. ओ. अब इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बाद

आदेश केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है

9-10-2002 पर नहर। रिपोर्ट में न्यूनतम मूल्यांकन किया गया है

गाद के भंडार को हटाने, सफाई के लिए लगभग दो वर्ष की अवधि पेड़ और झाड़ियाँ, क्षतिग्रस्त और संतुलन कार्यों को पूरा करना

और नहर को कार्यात्मक बनाना और एक राशि का अनुमान लगाया है की देनदारियों को छोड़कर इस उद्देश्य के लिए लगभग Rs.250 करोड़

पंजाब। इन परिस्थितियों में हम भारत संघ को निर्देश देते हैं कि निम्नलिखित समय सीमा के भीतर अपनी प्रस्तावित कार्य योजना को पूरा करनाः

1 ) भारत संघ एक केंद्रीय एजेंसी को जुटाने के लिए है

एक महीने के भीतर पंजाब से नहर के कार्यों का नियंत्रण

आज।

2 ) पंजाब को केंद्रीय एजेंसी को काम सौंपना चाहिए। 2 ( दो) सप्ताह बाद।

3 ) समन्वय के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए और

4 (चार) के भीतर डिक्री के शीघ्र कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करें आज से सप्ताह। हरियाणा राज्यों के प्रतिनिधि

और पंजाब को ऐसी समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

4 ) नहर के शेष भाग का निर्माण सहित

सर्वेक्षण, विस्तृत अनुमानों की तैयारी और अन्य तैयारी

मरम्मत, गाद निकालना, वनस्पतियों की सफाई आदि जैसे कार्य

केंद्रीय एजेंसी के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा। 97. हम इस अध्याय का समापन राज्य को एक अनुस्मारक के साथ करते हैं

पंजाब ने कहा कि "बड़े राज्यों का स्वभाव निजी राज्यों की तुलना में बेहतर है।

वादियों, और यह आशा की जानी चाहिए कि इसके लिए पर्याप्त निर्णय लिया गया है

देशभक्ति, संघ की बंधुत्व और आपसी विचार

इसे समाप्त करने के लिए "।

[ जोर दिया गया]

9. वनाच्छादित पृष्ठभूमि में, 12 जुलाई, 2004 को, राज्य o पंजाब अधिनियम, 2004 को [2016] 11 एस. सी. आर. को समाप्त करने के इरादे से अधिनियमित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31 दिसंबर, 1981 का समझौता और रावी और ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित अन्य सभी समझौते। उक्त अधिनियम के पीछे का उद्देश्य पंजाब सरकार को 31 दिसंबर, 1981 के वन समझौते के तहत उत्पन्न दायित्वों से मुक्त करना और यहां ऊपर निर्दिष्ट न्यायालय के फरमानों को रद्द करना भी था।

10. वनहीन तथ्य उन तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में कुछ और जानकारी देंगे जिनमें भारत के राष्ट्रपति ने वनहीन प्रश्नों को इस न्यायालय को अपनी राय के लिए भेजा है। 11. इस मोड़ पर, हम कुछ अनुचित घटनाओं का उल्लेख करना चाहेंगे जो इस संदर्भ को सुनने के बाद हुई थीं।

पंजाब राज्य के विधानमंडल ने पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर भूमि (स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण) विधेयक, 2016 पेश किया। आज तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं है और इसलिए, यह एक कानून नहीं है और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक बना रहेगा। वनों के कारण

पंजाब राज्य ने 31 दिसंबर, 1981 के समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कार्य करने का प्रस्ताव किया, जिसका उल्लेख संदर्भ में किया गया है।

12. पंजाब राज्य का इरादा सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित भूमि को अधिसूचित करने का था।

( इसके बाद पंजाब में "एस. वाई. एल. नहर" के रूप में संदर्भित किया गया और उक्त अधिनियम के अनुसरण में, पंजाब राज्य ने वापस लौटना शुरू कर दिया था।

एस. वाई. एल. नहर, जो निर्माण की प्रक्रिया में थी, को समतल करने, नष्ट करने और भरने के लिए पहले से ही उसके जमींदारों को अधिग्रहित भूमि और मिट्टी ले जाने वाले उपकरणों का कब्जा जुटाया गया था।

13. वनग्रस्त परिस्थितियों में, हरियाणा राज्य द्वारा 2016 का आई. ए. नंबर 7 दायर किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि अभियान और

पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर भूमि का कार्यान्वयन (हस्तांतरण) स्वामित्व अधिकार) अधिनियम, 2016 को निलंबित कर दिया जाए ताकि संदर्भ के अनुसरण में शुरू की गई पूरी कार्यवाही बाधित न हो। इसके बाद

संबंधित पक्षों की सुनवाई करते हुए, 17.3.2016 पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए विवश थाः

“ आई. ए. सं. 7/2016-उपयुक्त निर्देशों के लिए। बोर्ड पर लिया गया। आवेदन की सामग्री के अवलोकन पर और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने पर, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि यह देखने का प्रयास किया गया है कि

इस न्यायालय की एक डिक्री को अक्षम्य बनाया जा रहा है और यह न्यायालय उक्त तथ्य का मूक दर्शक नहीं हो सकता है और इसलिए, हम

!

इन आरईः पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

निर्देश दें कि अनुच्छेद (घ) (ii) में निर्दिष्ट निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

आवेदनः

" ( घ) (ii) एस. वाई. एल. नहर की भूमि, कार्य, संपत्ति और कुछ भाग और पंजाब राज्य के क्षेत्रों के भीतर एस. वाई. एल. नहर के संरेखण के भीतर सभी भूमि जो हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य, (2002) 2 एस. सी. सी. 507 (पैराग्राफ 18 और 19) और हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य, (2004) 12 एस. सी. सी. 712 (पैराग्राफ 96) में इस न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत आती हैं।

इन परिस्थितियों में, यह भी निर्देश दिया जाता है कि (i) सचिव, गृह विभाग, भारत संघ, (ii) मुख्य सचिव, पंजाब राज्य और (iii) पुलिस महानिदेशक, पंजाब राज्य को अदालत प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि पैरा (घ) (ii) में अनुरोध किया गया है और उक्त पैरा में निर्दिष्ट सभी संपत्तियों को उनमें निहित माना जाएगा और वे यह भी देखेंगे कि ऊपर उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी गई है। आवेदन पर जवाबी हलफनामे

28 मार्च, 2016 को या उससे पहले दाखिल किया जाए।

14. हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल और राज्यों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के), राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विद्वान वकीलों द्वारा अपने तर्कों को साबित करने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया गया था। हम नहीं करते। उद्धृत सभी निर्णयों को संदर्भित करने का प्रस्ताव; विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जिसे विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है, को विवादित नहीं किया जा सकता है और कुछ निर्णय हैं जो उन सभी मुद्दों को संदर्भित करते हैं जिनसे हम संबंधित हैं। हमने द्वारा निर्दिष्ट सभी निर्णयों की सभी प्रस्तुतियों और सार पर विचार किया है।

हम नीचे संक्षेप में उनके द्वारा की गई प्रस्तुतियों का उल्लेख कर रहे हैं।

15. चूंकि इस न्यायालय को संदर्भित सभी प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए सुविधा के लिए, हमने इसके बजाय एक साथ चर्चा की है।

16. पंजाब राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि यह संदर्भ के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के प्रावधान। उन्होंने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड में नहीं होने वाले तथ्यों के संबंध में कई मुद्दे भी शामिल हैं [2016] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यह उन कारणों में से एक है जिसके लिए इस न्यायालय को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय की ओर से प्रत्येक मामले में अपनी राय देना अनिवार्य नहीं है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय को भेजा जा सकता है। उनके अनुसार, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, विशेष रूप से जब कई अन्य आनुषंगिक तथ्य हैं

कुछ साल। उनके अनुसार, इस अदालत ने मुकदमा दायर करने का फैसला सुनाया था ऊपर उल्लिखित हरियाणा राज्य द्वारा, नदियों में पानी की आपूर्ति के संबंध में वास्तविक स्थिति उल्लेखनीय रूप से बदल गई है क्योंकि पानी की आपूर्ति में काफी कमी आई है, जिसने पंजाब राज्य के लिए समस्याएं पैदा की हैं और परिवर्तन को देखते हुए

उनके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार पंजाब राज्य के लिए एक अलग रुख अपनाना आवश्यक था और नई परिस्थितियों में पंजाब अधिनियम, 2004 को अधिनियमित किया जाना था और यह वैधानिक की ओर से अनिवार्य है। उक्त परिवर्तित परिस्थितियों पर विचार करने के लिए प्राधिकरण और यह न्यायालय और इसलिए, पंजाब अधिनियम, 2004 को अमान्य या भारत के संविधान के अधिकार से बाहर नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण का गठन पहले ही किया जा चुका है, पूरे मामले को न्यायाधिकरण को भेजना समीचीन होगा ताकि न्यायाधिकरण सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सके और उचित निर्णय ले सके।

निर्णय लें।

18. उन्होंने आगे कहा कि पंजाब राज्य पहले ही

न्यायाधिकरण के गठन के लिए एक अनुरोध के साथ एक मुकदमा दायर किया ताकि विवाद को न्यायाधिकरण को भेजा जा सके और विषम परिस्थितियों में,

संदर्भ का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर कानून इस बात के लिए स्पष्ट है कि जब भी पानी के बंटवारे के संबंध में कोई निर्णय होता है, तो परिस्थितियों में बदलाव आने पर निर्णय की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, यानी जब पानी का प्रवाह या पानी की आपूर्ति में बदलाव होता है। उनके अनुसार, बदली हुई परिस्थितियों में पहले के सभी आदेशों के अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर एक नया निर्णय आरई में होना चाहिए:

पंजाब समझौता अधिनियम की समाप्ति,

2004 [ ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

जल बंटवारे के संबंध में लिया जाए। पंजाब राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का योग और सार यह था कि यह संदर्भ बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि पंजाब राज्य द्वारा अधिनियमित कानून इसकी वैधानिक शक्तियों के भीतर है।

19. संदर्भ की वैधता के संबंध में मुख्य मुद्दे के जवाब में हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और

उनका समर्थन करने वालों ने कहा कि संदर्भ बनाए रखने योग्य है और पंजाब राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों में कोई सार नहीं है।

20. यह जांचने के लिए कि क्या ऐसा संदर्भ दिया जा सकता है, आइए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के प्रावधानों पर विचार करें,

जो नीचे लिखा है:

अदालत। --
( 1 ) यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को भेज सकता है और न्यायालय, इसके बाद, ऐसा कर सकता है।

( 2 ) राष्ट्रपति, अनुच्छेद 131 के परंतुक में कुछ भी होने के बावजूद, उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित प्रकार के विवाद का उल्लेख कर सकता है। राय के लिए उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया परंतुक, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय बताएगा।

21. संविधान के अनुच्छेद 143 के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि राष्ट्रपति इस न्यायालय को कानून या तथ्य के प्रश्न को संदर्भित करने के लिए अधिकृत हैं, जो उनकी राय में ऐसी प्रकृति का है और ऐसी सार्वजनिक है।

यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो। अनुच्छेद राष्ट्रपति को केवल राय प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है।

उस पर

पंजाब राज्य की ओर से यह कहना कि संदर्भ में तथ्य के कई प्रश्न शामिल हैं, इस प्रकार शायद ही प्रासंगिक है, क्योंकि एक राय कानून के सवाल पर और यहां तक कि तथ्य के सवाल पर भी पूछा जा सकता है।

22. यह सच है कि यह न्यायालय को तय करना है कि राष्ट्रपति को अपनी राय देनी है या नहीं और यह भी सच है कि इस तरह का विचार सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट रही है।

[ 201

6 ] 11 एस सी आर।

इस न्यायालय द्वारा लिया गया और किसी दिए गए मामले में यह न्यायालय अपनी राय देने से इनकार कर सकता है।

23. इसी मुद्दे पर विचार करते हुए, यह न्यायालय प्राकृतिक संसाधन आवंटन के मामले में, विशेष संदर्भ संख्या 1 के

2012 2012 ( 10 ) एस. सी. सी. 1 ने निम्नलिखित रूप में देखा हैः

" 35. जहां तक 2 जी मामले में फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा समीक्षा आवेदन दायर करने और वापस लेने के प्रभाव का संबंध है तत्काल संदर्भ की स्थिरता का संबंध है, यह रिकॉर्ड की बात है कि समीक्षा याचिका में, के कुछ पहलू

समीक्षा के लिए आधार जो संदर्भ के पाठ के साथ-साथ कुछ प्रश्नों में बताए गए हैं, उन पर प्रकाश डाला गया।

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत एक संदर्भ का जवाब देने में। समीक्षा मूल रूप से किसी निर्णय की समीक्षा के लिए सुव्यवस्थित सिद्धांतों और पक्षों के बीच पारित डिक्री या आदेश द्वारा निर्देशित होती है। न्यायालय समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वीकार्य और तय किए गए मापदंडों के तहत समीक्षा पर विचार कर सकता है। लेकिन, जब कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक शक्ति का सहारा लेते हुए इस न्यायालय की राय मांगी जाती है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह पूरी तरह से अलग है। समीक्षा विशिष्ट होती है और विवाद के पक्षकारों के अधिकारों से निपटा जाता है।

इसमें, जबकि एक संदर्भ का उत्तर संदर्भ की शर्तों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है और यह जांच की जाती है कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत नियोजित भाषा में निहित आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए, हमारे विचार में, केवल इसलिए कि एक समीक्षा दायर की गई थी और वापस ले ली गई थी और पाठ में

कथन उक्त मामले से संबंधित है, यह जवाब देने के लिए विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं होगी संदर्भ "।

24. इस प्रकार, यह इस न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर है, यह तय करने के लिए कुछ मापदंडों के अधीन है कि क्या किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना है। संदर्भ। इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, हमारी राय में यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार करना चाहे क्योंकि इसका कोई उचित कारण नहीं है।

25. इन परिस्थितियों में, हम पंजाब राज्य के विद्वान वकील द्वारा इस आशय के प्रस्तुतिकरण से सहमत नहीं हैं कि आई. एन. आर. ई.:

पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डी. ए. वी., जे.]

हमें अपनी राय केवल इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम संविधान के अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के तहत अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

भारत।

26. दूसरी ओर, हरियाणा राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने विभिन्न राज्यों के मुकदमे का इतिहास सुनाया।

संबंधित नदियों के जल बंटवारे का मुद्दा और प्रस्तुत किया गया

संक्षेप में यह कि पंजाब अधिनियम, 2004 को लागू करके, पंजाब राज्य उक्त राज्य के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा पारित फरमानों के प्रभाव को रद्द करना चाहता था। उन्होंने आगे कहा कि एक विधायी अधिनियम द्वारा, मुकदमे का एक पक्ष एक कानून नहीं बना सकता है जो एक डिक्री के प्रभाव को रद्द कर देगा।

न्यायालय द्वारा पारित किया गया और यदि ऐसी चीज की अनुमति दी जाती है, तो कानून के नियम के अनुसार हमारे लोकतंत्र का शासन खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि

भारत के संविधान में राज्यों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के तरीके का प्रावधान है। यदि हमारे जैसे संघीय ढांचे में, एक राज्य जिसके खिलाफ इस न्यायालय द्वारा एक डिक्री पारित की गई है, को डिक्री को रद्द करने के लिए कानून बनाने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप बहुत खतरनाक परिणाम होंगे और न्यायिक फैसले की अंतिमता को विकृत कर दिया जाएगा।

अनिश्चितता और इसके परिणामस्वरूप देश में कानूनी अराजकता हो सकती है। उन्होंने मुख्य रूप से री के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा कियाः कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, (1993) 1 सप. एस. सी. सी. 96 (II) और तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और दूसरा, (2014) 12 एस. सी. सी. 696। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है

और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की विधि। यदि संविधान में शामिल कानून का पालन नहीं किया जाता है तो देश में कानून का शासन नहीं होगा। उन्होंने कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख किया ताकि उनके मामले की पुष्टि की जा सके, मुख्य रूप से इस प्रभाव से कि इस तरह का कानून सरकार की विभिन्न शाखाओं के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून बनाने की विधायिका की शक्ति के भीतर नहीं होगा उच्चतम न्यायालय की डिक्री को निरस्त करने के लिए कानून।

27. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक बार के संबंध में एक समझौता

जल का बंटवारा किया गया था, यह प्रत्येक राज्य का कर्तव्य बन जाता है, जो समझौते का एक पक्ष है, समझौते का सम्मान करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए। तत्काल मामले में, न केवल एक समझौता है, बल्कि इस न्यायालय के आदेश भी हैं, जो इस तरह के अधिनियम को लागू करने पर रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस अदालत को पंजाब अधिनियम, 2004 की संवैधानिकता के खिलाफ राय देनी चाहिए और यह भी राय रखनी चाहिए कि पंजाब राज्य की ओर से समझौते के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है।

उसमें प्रवेश किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी भी कारण से पंजाब राज्य को लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण, नदियों के पानी को निर्धारित अनुपात में साझा करना संभव नहीं है।

समझौता या कोई डिक्री, पंजाब राज्य या कोई अन्य राज्य, जो समझौते का एक पक्ष है, को न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए। उचित आदेश ताकि उस अनुपात की समीक्षा के लिए आवश्यक कार्य किए जा सकें जिसके आधार पर जल बंटवारा समझौता किया गया था।

निष्पादित किया। उनके अनुसार, ऐसा करने के बजाय, पंजाब राज्य ने अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की है ताकि इस न्यायालय के आदेश को रद्द किया जा सके, जो तय किए गए कानून के विपरीत है।

29. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी राज्य को इस तरह से कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो हमारा संघीय ढांचा भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर देना। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि इस तरह के अधिनियम के परिणामस्वरूप अराजकता और कानूनी प्रणाली टूट जाएगी।

30. विभिन्न राज्यों की ओर से पेश अन्य वकीलों ने हरियाणा राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील का समर्थन किया है और उनके पास है

यह भी प्रस्तुत किया कि पंजाब राज्य पंजाब को अधिनियमित नहीं कर सकता था एक सक्षम न्यायालय की डिक्री को रद्द करने और समझौते के तहत अपने दायित्व से एकतरफा रूप से खुद को मुक्त करने के लिए कार्य करें।

31. विद्वान वकील को सुनने और मामले से संबंधित रिकॉर्ड को देखने और द्वारा उद्धृत निर्णयों के अवलोकन पर

विद्वान वकील, हमारा विचार है कि पंजाब अधिनियम नहीं हो सकता है कानूनी और वैध माना जाता है और पंजाब राज्य इस समझौते से उत्पन्न होने वाले अपने कर्तव्यों/देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है।

32. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह विवाद में नहीं है कि पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य के बीच एक मुकदमा था और

अंततः एक फरमान जारी किया गया जिसके तहत 31 दिसंबर, 1981 के समझौते के अनुसार पानी के बंटवारे के संबंध में व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार उक्त व्यवस्था के लिए एक कानूनी मंजूरी है और

एक बार कानून के न्यायालय द्वारा एक बाध्यकारी डिक्री पारित किए जाने के बाद, मुकदमे का एक पक्ष एकतरफा रूप से इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है जो डिक्री के प्रभाव को रद्द कर देगा।

33. तत्काल मामले में, उपयुक्त से संपर्क करने के बजाय

प्राधिकरण, अर्थात् उचित राहत के लिए न्यायाधिकरण, पंजाब राज्य ने पंजाब अधिनियम लागू करके अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग किया ताकि डिक्री के प्रभाव को रद्द किया जा सके।

आरईः पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]।

34. इसी तरह के मुद्दे से निपटने के लिए, यह न्यायालय राज्य के मामले में

आई. एन. यू. (ऊपर) ने माना है कि कोई राज्य "कानून के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ टकराव में जो प्राप्त हुआ है

टीआई। यदि किसी कानून ने स्थापित का उल्लंघन किया है

शक्तियों के पृथक्करण जैसी कानूनी सीमाएँ, इसे जाना होगा और

टी को रहने की अनुमति दी जाएगी "(पैरा 146)।

35. इस न्यायालय द्वारा आगे यह निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः

" 147. यह सच है कि राज्य के संप्रभु हित प्रदान करते हैं

सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की नींव लेकिन न्यायिक कार्य है

कानून के शासन की नींव। विधायिका आह्वान करके नहीं कर सकती है " सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत "या" एहतियाती सिद्धांत "अप्रत्यक्ष रूप से

न्यायालयों की कार्रवाई को नियंत्रित करना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलग करना

न्यायालय द्वारा तथ्य का आधिकारिक और बाध्यकारी निष्कर्ष,

( राज्य सरकार) मुकदमे में एक पक्ष थी और उन्हें सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाया गया।

XXX

XXX

XXX

149. मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच में यह न्यायालय

वी. भारत संघ [(2006) 3 एस. सी. सी. 643], राज्य की सुनवाई के बाद

इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। बल्कि, इसने तमिलनाडु को बढ़ने दिया। वर्तमान जल स्तर 136 फुट से बढ़कर 142 फुट हो गया और इसने केरल को नियंत्रित कर दिया।

पानी बढ़ाने में तमिलनाडु के अधिकार में हस्तक्षेप करने से

मुल्लापेरियार बांध का स्तर 142 फीट तक। इस प्रकार, एक निर्णय है

इस न्यायालय द्वारा दोनों राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा में दिया गया था

जल स्तर बढ़ाने के लिए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा का सम्मान

वास्तव में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद का निर्णय और अदालत में पेश किया गया। आवश्यक रूप से, ऐसा निर्णय होना चाहिए

पक्षों पर बाध्यकारी और के अनुसार लागू करने योग्य निर्णय लें। तथ्य पर एक सादा और सरल न्यायिक निर्णय नहीं हो सकता है।

दोनों राज्यों के बीच समझौतों को खत्म करने के लिए विधानमंडल "। संवैधानिक सिद्धांत कि विधायिका न्यायिक [2016] 11 एस. सी. आर. प्रदान कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय अपन विधायीक भीतर वैध कानून अधिनियमित कऽ अप्रभावी भऽ जायत छैक।

मूल रूप से अपने चरित्र को बदलना या बदलना पूर्वव्यापी रूप से कोई अनुप्रयोग नहीं है जहाँ एक न्यायिक निर्णय है

तथ्य की खोज को दर्ज करके प्रस्तुत किया गया। शक्ति के बहाने, विधायिका, के प्रभाव को बेअसर नहीं कर सकती है

साक्ष्य/साक्ष्य के माध्यम से तथ्य की पुष्टि के बाद दिया गया निर्णय

विवाद के पक्षकारों द्वारा रखी गई सामग्री। एक निर्णय जो तथ्यों पर निष्कर्ष देकर मामले का निपटारा करता है, वह विधायिका द्वारा परिवर्तन के लिए खुला नहीं है। एक अंतिम निर्णय, एक बार प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जाने तक कार्य करता है और लागू रहता है

उचित कार्यवाही।

150. 2006 (संशोधन) अधिनियम स्पष्ट रूप से रद्द करने का प्रयास करता है

इस न्यायालय का निर्णय जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। इसके अलावा, केरल द्वारा यह विवादित नहीं है कि 2006 (संशोधन) अधिनियम एक सत्यापन अधिनियम नहीं है। चूंकि विवादित कानून एक मान्य करने वाला कानून नहीं है, इसलिए यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सत्यापन करने में विधायिका ने उस दोष को हटा दिया है जिसे न्यायालय ने मौजूदा कानून में पाया है। मुल्लापेरियार बांध पर अपने अनुप्रयोग और प्रभाव में 2006 (संशोधन) अधिनियम काफी हद तक विधायी के अलावा एक अन्य कानून है क्योंकि इसका उद्देश्य इस न्यायालय के पूर्व और आधिकारिक निर्णय को रद्द करना है। उल्लंघन का मुख्य कारण केरल विधानमंडल द्वारा इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में संशोधन करना है, जो इस संवैधानिक सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना है कि इस तरह के अंतिम निर्णय का संशोधन बना रहना चाहिए।

विशेष रूप से अदालत के विवेक के भीतर "।

36. उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि एक मुकदमेबाजी

अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकते। उक्त सुविख्यात कथन को उक्त निर्णय के पैराग्राफ 158 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

इराः " 158. एक और पहलू यह है कि संघीय विवादों में, विधायिका (संसद और राज्य विधानमंडल) किसी अन्य राज्य के साथ किसी भी विवाद के मामले में अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। कानून का शासन जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है

संघ और राज्यों को कानून द्वारा किसी विवाद पर निर्णय लेने से रोकता है। दो राज्यों के बीच या संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच। यदि संविधान के तहत इसकी अनुमति दी गई थी, तो संघ और राज्य जिनके बीच कोई विवाद है, वे आपस में ऐसा करेंगे।

दूसरे के खिलाफ अपने दावे या अधिकार को स्थापित करने के लिए कानून बनाना और

इससे विरोधाभासी और अपरिवर्तनीय कानून बनेंगे।

द इन आरईः पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 [ए. एन. आई. एल. आर. डेव, जे.]

संविधान निर्माता किसी भी संभावना को दूर करने के लिए

अधिनियमित किए जा रहे विरोधाभासी और अपरिवर्तनीय कानूनों ने संघीय विवादों के स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रावधान किया है। अनुच्छेद 131

संविधान भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और एक तरफ के किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों के संबंध में इस न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

सवाल जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। अनुच्छेद 131 में संलग्न परंतुक संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान लिखत से उत्पन्न होने वाले विवाद के लिए इस न्यायालय की अधिकारिता के लिए एक अपवाद बनाता है जो संविधान के प्रारंभ से पहले दर्ज किया गया है या निष्पादित किया गया है और ऐसे प्रारंभ के बाद भी जारी है, जो प्रकृति में राजनीतिक हैं। में।

अंतर-राज्यीय नदी या नदी के जल से संबंधित विवाद का संबंध

घाटी, अनुच्छेद 262 उनके निर्णय के लिए न्यायाधिकरण या मंच के निर्माण का प्रावधान करता है। संघीय विवादों में, संसद या राज्य

यदि कानून द्वारा विधानमंडल दोनों राज्यों के बीच या संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विवाद का फैसला करना चाहते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 131 और 262 में प्रदान किए गए न्यायिक तंत्र को निरर्थक बना दिया जाएगा और -

इसलिए, ऐसा कानून संवैधानिक रूप से नहीं हो सकता है।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है।

37. अंत में, इस विषय पर, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 160 के तहत टिप्पणी कीः

" 160. जहां दो राज्यों के बीच किसी विवाद पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, जिससे निपटने का उसे अधिकार है।

रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा लेकिन क्योंकि यह उल्लंघन करता है शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन के सिद्धांत के रूप में, इस तरह के कानून द्वारा, विधायिका ने स्पष्ट रूप से न्यायिक शक्ति को हड़प लिया है। "

38. वनाच्छादित कानूनी स्थिति को देखते हुए, हमारी राय में, पंजाब राज्य ने अपनी विधायी शक्ति को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था

इस न्यायालय की डिक्री और इसलिए, पंजाब अधिनियम को एक वैध रूप से अधिनियमित विधान नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वनाच्छादित निर्णयों के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है।

[ 201

6 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. यह ध्यान देने योग्य है कि जल विवाद, जिसे पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य ने किया था, न्यायाधिकरण को भेजा गया था। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के संबंध में भी प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने

न्यायिक निर्णय लिया गया और उक्त निर्णय को पंजाब अधिनियम के अधिनियमन के आधार पर बाधित करने की भी मांग की गई है। 31 दिसंबर, 1981 का समझौता रावी और ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। उक्त समझौते को अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके समझौते के किसी भी पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता था और यदि कोई पक्ष या कोई राज्य ऐसा करता है, तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए।

तमिलनाडु राज्य (उपरोक्त) के मामले में, किसी विशेष राज्य की ऐसी एकतरफा कार्रवाई को भारत के संविधान के साथ-साथ अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत घोषित किया जाना चाहिए।

समझौते को समाप्त करने या देश के सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री को रद्द करने से पंजाब राज्य अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है जो 15 जनवरी, 2002 के फैसले और डिक्री और शीर्ष न्यायालय के 4 जनवरी, 2004 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होता है। 41. जंगली कारणों से, हमारी राय में, पंजाब अधिनियम को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है और उक्त अधिनियम के आधार पर पंजाब राज्य ऊपर निर्दिष्ट निर्णय और डिक्री को रद्द नहीं कर सकता है और 31 दिसंबर, 1981 के समझौते को समाप्त नहीं कर सकता है।

43. यह राय उच्चतम न्यायालय के भाग 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित की जाएगी। न्यायालय नियम, 2013।

शिवा कीर्ति सिंह, जे. अत्यधिक से गुजरने के बाद

अनिल दवे, जे., 1 का अच्छी तरह से तैयार किया गया निर्णय मेरे सम्मान को दर्ज करता है

उसी के साथ समझौता। लेकिन साथ ही इस संदर्भ में शामिल विवाद के तथ्यों और प्रकृति से मैं भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के स्वस्थ रखरखाव में रुचि रखने वाले सभी हितधारकों और विशेष रूप से भारतीय संघीय संरचना का हिस्सा बनने वाले राज्यों को हमारी संघीय व्यवस्था की विशिष्ट और आवश्यक विशेषताओं की याद दिलाने के लिए लुभाता हूं।

इन आरईः पंजाब करार की समाप्ति अधिनियम, 2004 [शिवा कीर्ति सिंह, जे.]

इन विशेषताओं के बारे में जागरूकता प्रणाली को स्वस्थ रखने और संवैधानिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उचित मार्ग पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का लेन-देन करने के लिए आवश्यक है। 2. उन निर्णयों का उल्लेख करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है जो हमें सबसे स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि भारतीय संविधान की परिकल्पना क्या है।

शासन का एक संघीय रूप लेकिन केंद्र की ओर एक स्पष्ट पूर्वाग्रह और स्पष्ट झुकाव के साथ। ऐतिहासिक रूप से, राज्यों की पूर्ण संप्रभुता नहीं थी। राज्यों के क्षेत्रों को बदला जा सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है और यहां तक कि उनके नाम भी बदले जा सकते हैं। वितरण के बावजूद

अनुच्छेद 246 द्वारा विधायी शक्ति, आपातकाल की स्थितियों को दरकिनार करते हुए, सामान्य समय के दौरान भी अनुच्छेद 248,249,251,252,253 और 254 जैसे प्रावधान राज्यों की सामान्य विधायी शक्तियों के विपरीत हैं। समवर्ती सूची के दायरे में आने वाले विषयों पर, किसी भी प्रतिकूलता के मामले में, संसद के कानूनों की राज्य विधानमंडल के कानूनों पर श्रेष्ठता होती है और वे प्रबल होते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ विधायी शक्तियों के साथ सुसंगत रूप से समाप्त होती हैं।

3. अत्यधिक महत्व का, हाथ में संदर्भ में सर्वोच्चता है

संविधान। अनुमेय सीमा तक भी, इसे केवल केंद्रीय संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान अनुदान देता है और मान्यता देता है

न्यायालयों को न केवल व्याख्या करने का बल्कि संविधान और कानूनों की रक्षा करने का भी सर्वोच्च अधिकार है। भारतीय मॉडल को केवल एक अर्ध-संघीय दिखाने वाली अन्य विशेषताओं के बावजूद, भारतीय संविधान एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका और एक अच्छी तरह से परिभाषित संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करके नियंत्रण और संतुलन बनाने में बहुत स्पष्ट और जोरदार है

कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्षों को हल करने के लिए तंत्र

संघ और राज्यों के प्राधिकार। भारतीयों ने खुद को एक संविधान और एक नागरिकता दी है। न्यायिक शक्ति है

उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर अदालतों के एकल समूह द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संवैधानिक शक्तियों के साथ राज्य स्तर पर अंतिम न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट निस्संदेह सर्वोच्च है।

सभी न्यायालयों-दीवानी, आपराधिक, राजस्व और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर अंतिम शक्तियों के समामेलन के साथ पदानुक्रम में न्यायालय। इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य न केवल अपीलीय पक्ष पर बल्कि संविधान के अनुच्छेद 32 और अन्य मूल क्षेत्राधिकारों जैसे संवैधानिक संदर्भों और मूल मुकदमों के तहत भी विशाल हैं जहां विवाद हो सकते हैं। राज्यों के बीच या संघ और राज्यों आदि के बीच हो।

4. हमारे संविधान के तहत उपर्युक्त व्यवस्था से यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं है कि कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या [2016] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका में निहित विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति को हड़प सकता है। इसके अलावा, एक परिणाम के रूप में, निर्णय और फरमान जो न्यायिक शक्ति के प्रयोग का अंतिम उत्पाद हैं, तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में विधायी घोषणा की प्रक्रिया द्वारा शून्य पर निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि मुख्य निर्णय में पहले ही समझाया जा चुका है, स्थिति कुछ अलग होती है जब एक सक्षम विधायिका किसी कानून को मान्य करने के अभ्यास में खुद को संलग्न करती है।

उन कारणों से दोषपूर्ण या अमान्य घोषित किया गया जो उपचार योग्य हैं।

5. कुछ परेशान करने वाले तथ्यों के कारण एक अवलोकन आवश्यक हैः

अंतिम निर्णय या डिक्री के निष्पादन में देरी, विशेष रूप से जब यह सर्वोच्च न्यायालय का हो, तो किसी भी प्राधिकरण द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह निश्चित रूप से देश की न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को कम करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे सभी संस्थानों को नुकसान होता है और

संविधान के तहत पदाधिकारी, संविधान के लिए भी हो सकते हैं।

संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

दिव्या पांडे

रा.

!

!